भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 25

उत्तर देने की तारीख 3 फरवरी, 2025
14 माघ, 1946 (शक)

लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 की तैयारी

25. श्री अनूप संजय धोत्रे:
श्री योगेन्द्र चांदोलिया:
श्री धर्मबीर सिंह:
श्री भोजराज नाग:
श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:
श्री प्रदीप कुमार सिंहः
श्रीमती कृति देवी देबबर्मन:
श्री खगेन मुर्मुः
श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2028 में होने वाले लॉस एंजिल्स ओलंपिक की तैयारी को देखते हुए देश के एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए अवसंरचनात्मक ढांचे और सुविधाओं में सुधार करने की योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार वर्ष 2028 के ओलंपिक की तैयारी करने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु निधि जुटाने के लिए किस प्रकार से निजी क्षेत्र और कॉर्पोरेट प्रायोजकों के साथ काम कर रही है;

(ग) क्या खेल और शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रमों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए कांकेर और बालोद में कोई नया खेल महाविद्यालय स्थापित करने का कोई विचार है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या इस वर्ष के बजट में उक्त महाविद्यालय की स्थापना की घोषणा किए जाने की संभावना है; और

(ङ) क्या सरकार के पास कांकेर बस्तर संभाग में खेलों को बढ़ावा देने के लिए बजट प्रावधान करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) खेल राज्य का विषय होने के कारण देश में खेलों को बढ़ावा देने/विकसित करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है जिसमें खेल सुविधाएं प्रदान करना भी

शामिल है । तथापि, केंद्र सरकार अपनी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से देश में खेलों को बढ़ावा देने/विकसित करने के लिए उनके प्रयासों में सहायता करती है, जिसमें विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खेल सुविधाएं प्रदान करना शामिल है, जैसे कि:

(i) खेलो इंडिया स्कीम;

(ii) भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्र;

(iii) राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ)

इसके अलावा, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत स्वायत्त निकाय, भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) केवल साई केंद्रों में अवसंरचना निर्माण/उन्नयन करता है।

इसके अलावा, देश भर में खेलो इंडिया स्कीम के तहत स्वीकृत खेल अवसंरचनाओं का विवरण मंत्रालय के डैशबोर्ड https://mdsd.kheloindia.gov.in पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

(ख) भारत सरकार ने सीएसआर पहल के तहत निजी क्षेत्र की संस्थाओं और कॉर्पोरेट प्रायोजकों के साथ सक्रिय सहभागिता करके 2028 ओलंपिक की तैयारी के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (एमवाईएएस) की राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) के तहत, सरकार नियमित रूप से कॉर्पोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ बातचीत कर रही है और उनसे एनएसडीएफ में योगदान देने और देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय भागीदार बनने का अनुरोध कर रही है। एनएसडीएफ खेल विकास के लिए निजी योगदान और कॉर्पोरेट फंडिंग जुटाने के लिए एक महत्वपूर्ण चैनल के रूप में कार्य करता है। इस निधि में कॉर्पोरेट्स द्वारा किए गए योगदान को कर लाभ के साथ प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे अधिक भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। एनएसडीएफ के माध्यम से एकत्र की गई धनराशि का उपयोग अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर प्रदान करने और विश्व स्तरीय कोचों को नियुक्त करने के लिए किया जाता है।

(ग) से (ङ) : जी नहीं।

****